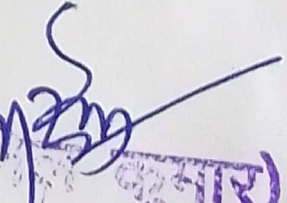


24

पत्रावली पेश हुई। वकील ऊपीलान्ट उपो।
 वकील ऊपीलान्ट की बहल सुनी गई।
 वकील ऊपीलान्ट की बहल पर मनन
 किया गया। पत्रावली व पत्रावली में
 उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन किया
 गया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट का
 रिपोर्ट परिवारी हल्का का अवलोकन करने
 पर पाया गया कि ऊपीलान्ट द्वारा भूमि
 खण्ड न० 2491/2 रुकबा 8.67 ई. कि एम चारागाह
 में से 0.05 में पुराना मकान बनाकर अति
 कुमठ किया जाना बताया है। ऊपीलान्ट
 का मुख्य कथन यह है कि अधिनस्थ
 न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से

(
 अतिरिक्त (कमल कुमार)
 नीमकाधाना कलक्टर

पूर्व अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का को
 अवसर नहीं दिया गया। अधिनियम न्यायालय
 द्वारा अपीलान्ट को जो दिनांक 11-11-2016
 को नोटिस जारी किया जिसमें 28-11-2016
 के लिए जारी किया था। पत्रवली में
 उपलब्ध नोटिस पर ना ले डिली प्रमाण
 के स्पष्ट दस्तावेज हैं एवं ना ही नार्मल
 कुन्निदा की रिपोर्ट कि हुई है। इससे यह
 प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को नार्मल
 प्रोपर नहीं हुई है एवं निर्णय पारित करने
 में शिथिलता दिखाई जाना प्रतीत होगा
 इसी के साथ सुनवाई का अवसर
 भी नहीं दिया गया। पत्रवली में उपलब्ध
 इन्दिया कावास योजना स्वीकृति फाइल की
 फोटो प्रति के अवलोकन से यह तो स्पष्ट
 है कि इस योजना के तहत अपीलान्ट को
 राशि प्राप्त हुई है। अधिनियम न्यायालय
 द्वारा दिनांक 28-11-2016 को जो निर्णय
 पारित किया गया है जो केवल प्रोफार्म
 में अलग से अंकन कर निर्णय पारित
 किया गया है। अपीलान्ट द्वारा बिजली का
 बिल भी पेश किया गया है। पटवारी
 हल्का द्वारा रिपोर्ट के फिदे जो नजरी
 नम्बरा बनाया है जिसमें चारों दिशाओं
 का माप भी अंकन नहीं किया है।
 अधिनियम न्यायालय द्वारा जो निर्णय
 पारित किया गया है जिससे यह तो स्पष्ट
 रूप से साबित होता है कि निर्णय इसी
 पेशी पर ही पारित किया है। इससे यह
 स्पष्ट है कि निर्णय पारित करते समय
 रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन नहीं
 किया गया है। ना ही पूर्ण सुनवाई का
 अवसर दिया गया है। अधिनियम न्यायालय
 कि पत्रवली के अवलोकन से स्पष्ट है
 कि पत्रवली में कई कृदिया पाई गई हैं।

(हस्ताक्षर)
 बतिया
 कलक्टर

जो इस दुकम की तारीख में जारी है

दुकम या कार्यवाही मय इन्डियन जज

नंबर व तारीख अहम
जो इस दुकम की तारीख में जारी हुए

तारीख
दुकम

इपीलाट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो इन्वाईस्टेड नोटिस जारी किया गया था जिसे अनुसार प्रोपर तामिल नही होने के कारण ही इपीलाट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कि जाकर निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। बिना प्रोपर तामिल के एक पक्षीय कार्यवाही कि जाना विधि विरुद्ध है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय कि पत्रवली में कई त्रुटियां पाई जाने से इपील इपीलाट - न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इपील इपीलाट साबित होने से स्वीकार की जाती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मजीत गढ के मुं नं 313/2016 उनवारी सरकार बनाम हाभा में पारित आदेश दिनांक 28-11-2016 इपास्त किया जाता है तथा इपील इपीलाट नायब तहसीलदार मजीत गढ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि इपीलाट को इन्वाईस्टेड पूर्ण अवसर दिया जाके एवं प्रकृता में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया जाकर एवं मांके पर सही नाप जोख कि जाकर इपता निर्णय पुनः पारित किया जावे। निर्णय कि पालना हेतु नायब तहसीलदार मजीत गढ को तहरीर जारी कि जावे। पत्रवली फंसल नुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल कर लें।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीमनाथाना